लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

"विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए।
: एपीजे अब्दुल कलाम

पाक्षिक 1-15 जुलाई 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक-21

भजन संध्या के जरिए श्रद्धांजलि 3

शहद कारोबारियों के लिए मधुक्रांति पोर्टल 6

शिवालिक की पहाड़ियों में पर्यटन 7

पानी है अनमोल

मनोज प्रभाकर

प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है। इसके लिए न केवल नहरी पानी की पर्याप्त उपलब्धता पर ध्यान दिया जा रहा है बल्कि हर घर तक नल से जल पहुंचाने की कवायद पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।

नल से जल योजना के अंतर्गत हरियाणा के आठ जिलों को पूर्ण रूप से कवर किया जा चुका है और शीघ्र ही सभी जिलों को कवर करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। अटल भूजल योजना के अंतर्गत हरियाणा के 1,669 गांवों में भूजल का स्तर दर्ज करने की दिशा में पीजोमीटर लगाए जाएंगे और जल के पूर्ण सदुपयोग की योजनाएं तैयार की जाएंगी।

'जल जीवन मिशन' के तहत सभी परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से हो रहे कार्यों को देखते हुए केंद्र में हरियाणा सरकार की सराहना हुई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के लिए 1,119.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन में हरियाणा देश के प्रथम तीन राज्यों में शामिल है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय में नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक की जिसमें केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले 130 गांवों में 55 लिटर की अपेक्षा 130 लिटर प्रति व्यक्ति की दर से पेयजल उपलब्ध करवाने तथा सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य के प्रत्येक महाग्राम के लिए 25 करोड़ रुपए की दर से कुल 3,250 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है।

जल संरक्षण के प्रति सजगता

राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण व फसल विविधिकरण के प्रोत्साहन के लिए बीते वर्ष चलाई गई 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच से बनी महत्त्वपूर्ण योजना के तहत 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि व जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

झज्जर जिला में गांव ढाकला के किसानों ने इस बार सामूहिक रूप से अपने खेड़े की 3,445 एकड़ भूमि में धान की खेती नहीं करने का निर्णय लिया है। जबकि बीते वर्ष गांव के तीन हजार एकड़ रकबे में धान लगाई गई थी। गांव के किसानों का मानना है कि धान में पानी की अधिक खपत से फसल की लागत तो बढ़ती ही है, साथ ही भूजल का भी अत्यधिक दोहन होता है। जबकि अन्य फसलो में कम लागत होने व सरकार की प्रोत्साहन राशि से पैसा और पानी दोनों की बचत होगी।

गिरते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का कहना है कि आज हरियाणा के 36 खण्ड डार्क जोन में आ चुके हैं। अगर जल संरक्षण के प्रति आज सजगता नहीं बरती गई तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। बीते वर्ष भी राज्य की 95 हजार एकड़ भूमि में धान की बजाए कम पानी से होने वाली फसलों की खेती की गई थी। प्रदेश में 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत एक लाख 13 हजार 885 किसान अब तक एक लाख 26 हजार 928 हैक्टेयर में धान की बजाए अन्य कम लागत वाली फसलों की खेती कर रहे हैं।

धान की फसल नष्ट करने वाले किसान संतराम व जयपाल ने पंचायत की जमीन पट्टे पर लेकर इस बार धान लगाई थी लेकिन जल संरक्षण के प्रति गांव में बनी जागरूकता व हरियाणा सरकार की 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना से उन्होंने अपनी फसल नष्ट करने का निर्णय लिया। किसान सुरेंद्र व रामरतन ने बताया कि किसानों ने पानी की अहमियत समझी है। अगर पानी को आज नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट खड़ा हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी होगी।

गहराता जल संकट

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुताबिक प्रदेश के 22 जिलों में से 14 जिलों में भूजल दोहन से उत्पन्न समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। सात जिलों में जल भराव तथा जलीय लवणता की समस्या है। भूजल दोहने के कारण वर्ष 2004 में राज्य के 114 ब्लॉक में से 55 ब्लॉक रेड जॉन में आ चुके थे जो करीब 48 फीसद थे। 2020 में 141 ब्लॉक में 85 ब्लॉक रेड जॉन में पहुंच गए जो 60 प्रतिशत हैं। इसलिए किसानों को चाहिए कि भूजल की निर्भरता कम की जाए और फसल विविधितता को प्राथमिकता दें।

नदी को यूं ही नहीं मां का दर्जा दिया गया है। सभ्यताओं की बसासत नदियों के तट पर होती रही है। आज नदियों की धारा कमजोर पड़ चुकी हैं, अनेक बिंदुओं पर तो धाराओं के केवल निशान बचे हैं। 55 फीसद कुएं सूख चुके हैं। तालाब तालाब नहीं रहे, बावड़ी व अन्य जलाशय भी निरंतर सूखते जा रहे हैं। बढ़ती गर्मी से यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। खेती के ट्यूबवैलों के अलावा घर-घर लग चुके और लग रहे सबमर्सिबलों ने भूजल का पूरी निर्ममता से दोहन किया है। इन पर किसी का नियंत्रण भी नही रहा। जागरूकता के अभाव में पानी का जमकर दुरुपयोग हो रहा है जिससे भूजल स्तर पाताल की ओर अग्रसर है। सरकारों को चाहिए कि इनके संचालन पर सरकारी नियंत्रण रखा जाए। उपलब्ध पानी का 50 फीसद हिस्सा खेती में, 10 फीसदी उद्योग में व 5 फीसदी घरों में इस्तेमाल होता है।

जल जीवन का महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिछले कुछ दशकों से भूमिगत जल का दोहन अंधाधुंध हुआ है जिसकी वजह से धरती पर जल संकट खड़ा हो गया है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक जल संकट और विकट हो जाएगा। भारत में दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर व हैदराबाद में पेयजल की सबसे अधिक समस्या है। कैपटाऊन में पेयजल राशन कार्ड में मिलने लगा है। जल संरक्षण पर दीर्घकालीन योजनाएं बन रही है लेकिन आम आदमी इनके प्रति गंभीर नहीं है। जितना संभव हो सके पानी बचाना होगा वरना आक्सीजन संकट की तरह जल संकट से जूझना पड़ सकता है।

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण

प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकारण के पास सतही जल, भूजल और संशोधित व्यर्थ पानी सहित जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन की जिम्मेवारी होगी, जिसका अधिकार क्षेत्र समस्त राज्य होगा।

राज्य में किसी भी प्रभावी कानून के अभाव में पानी के अनियंत्रित और तेजी से उपयोग के कारण कई क्षेत्रों में सतही जल की कमी के साथ भूजल स्तर में गिरावट की चिंतनीय स्थिति पैदा हो गई है। भविष्य में गंभीर जल संकट और पानी के अत्यधिक दोहन की स्थिति से निपटने के लिए राज्य में पानी की सुरक्षा, संरक्षण, नियंत्रण एवं उपयोग को नियमित करने के लिए एक उचित कानून बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि राज्य में विशेष रूप से तनावग्रस्त क्षेत्रों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से स्थायी रूप में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके।

प्राधिकरण के पास सिविल कोर्ट की शक्ति यां भी होंगी और प्राधिकरण के आदेशों या निर्देशों का पालन न करना धारा 22 के तहत दंडनीय होगा। विधेयक की धारा 25 के तहत अनधिकृत कृत्यों के लिए दंड के साथ-साथ धारा 26 के तहत जुर्माने का भी प्रावधान है। प्राधिकरण द्वारा हर तीन वर्ष बाद प्रत्येक जिला के लिए तैयार जल योजनाओं के आधार पर एक एकीकृत राज्य जल योजना तैयार की जाएगी।

संपादकीय

'डेल्टा प्लस वरिएंट' से सावधानी ज़रूरी

यद्यपि जीवन पटरी पर धीरे-धीरे लौट रहा है लेकिन कोरोना की तीसरी लहर एवं 'डेल्टा प्लस वरिएंट' ने चिंता फिर से जगा दी है। यह चिंता केवल इतनी ही मांग करती है कि भयातीत भी न हों और सावधानी का दामन भी न छोड़ें।

शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के 'डेल्टा प्लस वेरिएंट' के, देश में अब तक 40 मामले मिल चुके हैं। कोविड कार्यबल का कहना है कि अभी भी इसे लेकर चिंता करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। यह भी चिंता की बात है। अव्वल तो कोरोना के किसी भी मामले को गणना से वंचित नहीं रहने देना चाहिए और शुरुआती रूप से बहुत खतरनाक बताए जा रहे डेल्टा प्लस के मामलों के प्रति तो और सजग रहने की जरूरत है। एक-एक मामला दर्ज होना चाहिए ताकि उसकी निगरानी व इलाज में सुविधा हो। इस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि रोगी को फौरन क्वारंटीन किया जाए ताकि उसके इलाज व उस पर होने वाले चिकित्सकीय शोध से सुनिश्चित लाभ मिले और इस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके।

ध्यान रहे, डेल्टा वेरिएंट को हम शुरू में रोकने में नाकाम रहे और इससे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। 'डेल्टा प्लस' के समय में हमें वही गलती दोहराने से बचना चाहिए। कोविड-19 कार्यबल ने उचित ही चेताया है कि लोगों को कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने, मास्क पहनने, भीड़ से बचने और टीका लगवाने की अभी भी जरूरत है। लेकिन आज यह बड़ा खुलासा है कि क्या लोग दिशा-निर्देशों की पालना कर रहे हैं? कितने लोग मास्क पहन रहे हैं? क्या टीका लगाने या लगवाने में तेजी आई है? यह बहुत अफसोस की बात है कि हम तीसरी लहर की आशंका के बावजूद उतने सतर्क नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। अत्यधिक संक्रामक माने जा रहे 'डेल्टा प्लस' के 21 मामले अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं।

महाराष्ट्र व्यावसायिक रूप से देश का नेतृत्व करने वाला राज्य है इसलिए उसका देश के सभी राज्यों से भरपूर जुड़ाव है। अतः मुंबई और महाराष्ट्र में ही अगर इस वेरिएंट को रोकने की कवायद ईमानदारी से की गई तो इसे बेकाबू होने से रोका जा सकेगा।

आधिकारिक रूप से हरियाणा अभी सुरक्षित है लेकिन मध्यप्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। क्या इन राज्यों में सतर्कता बढ़ी है? क्या दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो रहा है? लोगों को लगातार जागरूक करते रहना होगा। सबसे जरूरी है कि चिकित्सक सावधान और तैयार रहें। अभी इस वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने की चर्चाएं भी की जा रही है, पर यह कितना खतरनाक होगा, अभी चिकित्सक स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। संक्रमित लोगों के आंकड़ों के अध्ययन से ही इस वेरिएंट की गंभीरता का अंदाजा लगेगा। विशेषज्ञ यथाशीघ्र इसकी गंभीरता का ठोस पता लगाए और बचाव व इलाज पर पूरी मुस्तैदी से जोर दिया जाए तो हम तीसरी लहर को खतरनाक बनने से रोक सकेंगे।

- डा चंद्र त्रिखा

लाल डोरा मुक्त होते गांव

हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि पूरे हरियाणा में स्वामित्व योजना का कार्य आगामी 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करके गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिये और कहा कि पूरी लगन व समर्पित भाव से इस योजना को सिरे चढ़ाने का काम किया जाए।

उन्होंने बताया कि इस योजना को सबसे पहले हरियाणा में लागू किया था तथा उसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना की खूबी को देखते हुए पूरे देश में लागू किया। उन्होंने बताया कि यह योजना अब पूरे देश में लागू की जा चुकी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस योजना को सबसे पहले हरियाणा अपने यहां पूरा करेगा।

कौशल ने हरियाणा के साथ लगती उत्तर प्रदेश सीमा पर सीमांकन के संबंध में बताया कि करनाल के साथ लगती यूपी की सीमा पर 20 स्थानों पर पिल्लर लगाने का कार्य आगामी 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के साथ लगती हरियाणा की सीमा के क्षेत्र का स्ट्रिप मैप भी तैयार करें ताकि जल्द से जल्द विवादों को निपटाया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही दस ड्रोन भी खरीदे जाएंगे ताकि स्वामित्व पयिोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

- संगीता शर्मा

ग्रामीणों को मिलेगा मालिकाना प्रमाणपत्र

राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन ही स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गांव की जमीन की वैज्ञानिक तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए माप या पैमाइश की जाएगी। वास्तव में, स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों के सही आकलन करने का प्रयास है, जिसके तहत देश के सभी गांवों की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी और गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

इससे संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी रहती है वो एक हद तक दूर हो जाएगी। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग सही तरीके से होगी। अब शहरों की तरह ही गांवों में भी ग्रामीण बैंकों से ऋण ले सकते हैं क्योंकि जब ग्रामीणों के पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर ये बैंक से ऋण ले सकेंगे।

ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गांव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली, भवन निर्माण के लिए परमिट जारी करने और अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है।

मंत्रिमंडल की बैठक

अब डीलर के माध्यम से पंजीकृत होंगे वाहन

हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में किए जा रहे संशोधनों के साथ ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पूरी तरह से निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलरों के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से वाहन मालिक अपने पूर्ण रूप से निर्मित नए परिवहन वाहनों को संबंधित डीलर के माध्यम से पंजीकृत करवा सकेंगे। यह प्रक्रिया कैशलैस और फेसलैस होगी। इससे पंजीकरण प्राधिकरणों के कार्यालयों में लोगों की आमद में उल्लेखनीय कमी आएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक मंत्रिमंडल ने नियम-33 के मौजूदा उप-नियम (3) में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन के अनुसार, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम-33 के मौजूदा उप-नियम (3) में 'गैर-परिवहन' शब्द और सकेत को हटाया जाएगा।

वाहनों का पंजीकरण डीलरों द्वारा ऑनलाइन भी किया जा सकेगा, जैसा कि वर्तमान में नए गैर-परिवहन वाहनों के मामले में किया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 48.80 लाख से अधिक नए निजी वाहन पंजीकृत हुए हैं। प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को डाक द्वारा भेजा जाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण नियम बनाने की स्वीकृति

हरियाणा में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल के कुछ विशेष निर्णय

हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है। संशोधन के अनुसार, स्टेनो-टाइपिस्ट के पद की योग्यता के संबंध में, अंग्रेजी शॉर्टहैंड की शर्त को '64 शब्द' प्रति मिनट के स्थान पर '80 शब्द' किया गया है।

- 'वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 'समाधान से विकास' को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने और नीति के लाभ का विस्तार सीएलयू परमिशन तक करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमन, 2018 के विनियमन 3 में उपयुक्त संशोधन करके, आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष के अलावा, मौजूदा 8 से घटाकर 5 कर दी गई है।

नंबरदारों को जल्द मिलेंगे स्मार्ट फोन

उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि नंबरदारों का पद खत्म नहीं किया जाएगा, वे निर्धारित रहेंगे। यही नहीं अपितु भविष्य में राज्य के नंबरदारों को हर माह एक निश्चित तिथि को मानदेय दिया जाएगा ताकि उनको कई-कई माह तक इंतजार न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है तथा जल्द ही स्मार्ट फोन भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला ने नंबरदारों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि नंबरदार की हमारे समाज में एक अलग पहचान व सम्मान होता है। उन्होंने नंबरदारों को अच्छे सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनको गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर आदि पर होने वाले सोशल-ऑडिट में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थानों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं में नंबरदार क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे भी नंबरदार सुझाव दें ताकि समाज के विकास में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अगर ज्यादा भागीदारी होगी तो नंबरदार के मानदेय में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकेगी तथा तहसील स्तर पर उनको बैठने व काम करने के लिए एक स्पेशल कमरा दिया जा सकेगा।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि 'प्रगतिशील किसान सम्मान' हर जिला अनुसार एवं प्रदेश स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। प्रगतिशील किसान हर वर्ष दस-दस और किसानों को ट्रेनिंग दें। ताकि प्रगतिशील किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके।

डिपो-होल्डरों के माध्यम से ब्रांडिड एफएमसीजी कंपनियों का सामान उचित दामों पर बिक्री की योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, और पंचकूला जिलों को शामिल किया गया है।

कबिरा, मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर

कबीर, सूरदास व तुलसीदास जिस कालखंड में आते हैं, वह भक्तिकाल का स्वर्ण युग कहलाता है। इन तीनों में मात्र एक ही अंतर था। कबीर अपनी रचनाओं में सूर व तुलसी की अपेक्षा सामाजिक सरोकारों की ओर अधिक उन्मुख थे। जबकि महाकवि सूरदास और महाकवि तुलसीदास कृष्ण व राम के माध्यम से जीवन का हर कोना प्रकाशमान करते थे। उस काल में सगुण व निर्गुण, दो ही मुख्य भक्ति धाराएं थीं। ये दोनों सगुण मार्गी थे जबकि कबीर निर्गुण मार्गी माने जाते हैं।

निर्गुण मार्ग में भी दो प्रमुख शाखाएं थीं। एक शाखा ज्ञानमार्गियों की थी जबकि दूसरी शाखा प्रेममार्ग की।

फ़कीरी, चिंतन, ज्ञान, प्रेम, वैराग्य, हठयोग व समर्पण भाव के अनूठे मिश्रण थे संत कबीर।

भक्तिकाल के सभी अन्य संत कवियों की तरह कबीर के जन्म व मरण के विषय में भी कोई लिखित अथवा प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी निष्कर्ष हैं वे सब अन्तः साक्ष्यों व बाह्य साक्ष्यों पर आधारित हैं। अधिकांश विद्वानों का निष्कर्ष यही है कि कबीर का जन्म सम्वत् 1456 में और मृत्यु संवत 1575 में हुई थी। अर्थात् अपने समय का यह महान फकीर 119 वर्ष तक जिया।

कबीर की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी अनेकों दंतकथाएं हैं। डॉ. श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित एक दन्तकथा के अनुसार काशी में एक सात्विक ब्राह्मण रहते थे जो स्वामी रामानंद जी के बड़े भक्त थे। उनकी एक विधवा कन्या थी। उसे साथ लेकर एक दिन वे स्वामी जी के आश्रम पर गए। प्रणाम करने पर स्वामी जी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवता ने चौंककर जब पुत्री का वैधव्य निवेदन किया तब स्वामी जी ने सखेद कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं जा सकता, परंतु इतने से संतोष करो कि इससे उत्पन्न पुत्र बड़ा प्रतापी होगा। आशीर्वाद के फलस्वरूप जब इस ब्राह्मण कन्या को पुत्र उत्पन्न हुआ तो लोक लज्जा और लोकापवाद के भय से उसने उसे एक तालाब के किनारे डाल दिया। भाग्यवश कुछ ही क्षण के पश्चात नीरू नाम का एक जुलाहा अपनी स्त्री नीमा के साथ उधर से आ निकला। इस दंपति के कोई पुत्र न था। बालक का रूप पुत्र के लिए लालायित दम्पति के हृदय में चुभ गया और वे इसी बालक का भरण-पोषण कर पुत्र वाले हुए। आगे चलकर यही बालक परम भगवद्भक्त कबीर हुआ। कबीर का विधवा ब्राह्मण कन्या का पुत्र होना असंभव नहीं किन्तु स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद की बात ब्राह्मण कन्या का कलंक मिटाने के उद्देश्य से ही पीछे से जोड़ी गई जान पड़ती है, जैसे कि अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के संबंध में जोड़ी गई है।

मुसलमान घर में पालन होने पर भी कबीर का हिन्दू विचारों में सराबोर होना उनके शरीर में प्रवाहित होने वाले ब्राह्मण अथवा कम से कम हिन्दू रक्त की ही ओर संकेत करता है। स्वयं कबीरदास ने अपने माता-पिता का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है और जहां कहीं उन्होंने अपने संबंध में कुछ कहा भी है वहां अपने को जुलाहा और

बनारस का रहने वाला बताया है-

'जाति जुलाहा मति को धीर। हरषि हरषि गुण रमै कबीर/
मेरे राम की अधैपद नगरी, कहै कबीर जुलाहा/
तू ब्राह्मन मैं काशी का जुलाहा।'

इस बात के प्रमाण कबीर की रचनाओं में ही मिल जाते हैं कि वे अपने समय के महान संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। प्रचलित मान्यता यही है कि कबीर जब घाट पर जाकर उपदेश देने लगे तो किसी ने कह दिया कि इन उपदेशों को तब तक मान्यता नहीं मिल सकता जब तक कबीर स्वयं किसी गुरु की शरण में नहीं जाते।

कहते हैं, उस समय स्वामी रामानंद जी काशी में सबसे प्रसिद्ध महात्मा थे। अतएव कबीर उन्हीं की सेवा में पहुंचे। परंतु उन्होंने कबीर के मुसलमान होने के कारण उनको अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। इस पर कबीर ने एक उपाय अपनाया जो अपना काम कर गया। रामानंद जी पंचगंगा घाट पर नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करने जाया करते थे उस घाट की सीढ़ियों पर कबीर पहले से ही जाकर लेट गए। स्वामी जी जब स्नान करके लौटे तो उन्होंने अंधेरे में इन्हें न देखा। उनका पांव इनके ऊपर पड़ गया जिस पर स्वामी जी के मुंह से 'राम राम' निकल पड़ा। कबीर ने चट उठकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि राम-राम का मंत्र देकर आज से मेरे गुरु हुए हैं। रामानंद जी से कोई उत्तर देते न बना। तभी से कबीर ने अपने को रामानंद का शिष्य प्रसिद्ध कर दिया।

उधर कबीर के अनुयायियों में मुस्लिमों की भी भारी संख्या थी। मुस्लिम कबीरपंथी उन्हें सूफी फ़कीर शेख तकी का शिष्य बताते हैं। कबीर ने अपने गुरु के बनारस निवासी होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस कारण पीर शेख तकी उनके गुरु नहीं हो सकते थे। 'घट घट है अविनासी सुनहु तकी तुम शेख' में उन्होंने तकी का नाम उस आदर से नहीं लिया जिस आदर से गुरु का नाम लिया जाता है और जिसके प्रभाव से असंभव का भी संभव होना लिखा है।

'गुरु प्रसाद सूई कै नोकै हस्ती आवै जाहि।।'

बल्कि वे तो ऊंटे तकी को ही उपदेश देते हुए जान पड़ते हैं। यद्यपि यह वाक्य इस ग्रंथावली में कहीं नहीं मिलता फिर भी स्थान-स्थान पर 'शेख' शब्द का प्रयोग मिलता है जो विशेष आदर से नहीं लिया गया है, वरन् जिसमें फटकार की मात्रा ही अधिक देख पड़ती है। यह हो सकता है कि कबीर कुछ समय तक उनके सत्संग में रहे हों, जैसा कि नीचे लिखे वचनों से भी स्पष्ट होता है-

'मानकिपुरहिं कबीर बसेरी/मदहति सुनि शेख तकि केरी/
ऊजी सुनी जौनपुर थाना/झूसी सुनि पीरन के नामा//'

परंतु इसके अनंतर भी वे जीवनपर्यंत राम नाम रटते रहे जो स्पष्टतः रामानंद के प्रभाव का सूचक है, अतएव स्वामी रामानंद को कबीर का गुरु मानने में कोई अड़चन नहीं है, चाहे उन्होंने स्वयं उन्हीं से मंत्र ग्रहण किया हो अथवा उन्हें अपना मानस गुरु बनाया हो। उन्होंने किसी मुसलमान फकीर को अपना गुरु बनाया हो इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता।

संतों, योगियों, हठयोगियों व चिंतकों की संगति ने कबीर को एक नया रूप दिया। उनके शब्दों में 'ज्ञान से मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है।'

'कबिरा, मन निर्मल भया/जैसे गंगा नीर
पाछे पाछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर'

-संवाद ब्यूरो

भजन संध्या के जरिए श्रद्धांजलि

संत कबीर दास की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संत कबीर जी के शांति और सद्भाव के संदेश को सुनाने वाले पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया और उनकी टीम कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ में भजनों की प्रस्तुति देते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर दास को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि विश्व को मानवता और प्रेम का पाठ भी सिखाया। मैं महान संत कबीर दास जी को नमन करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब संत कबीर दास जी द्वारा दिखाए गए श्रद्धा, भक्ति, समानता और करुणा के मार्ग पर चलकर समाज के बंधनों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहें।

जाति-पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई -दोहे को बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर दास किसी विशेष जाति या समुदाय के नहीं बल्कि पूरे समाज के थे। उन्होंने सदैव मानवता की भलाई के लिए कार्य किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कबीर वाणी के विश्व विख्यात गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया और उनके समूह को पवित्र भगवद गीता भेंट कर सम्मानित किया।

दुलहनी गावहु मंगलचार,
हम घरि आए हो राजा राम भरतार
मन रत करि मैं तन रत करिहूं, पंचतत बराती
रामदेव मोरें पांहुनें आए मैं जोबन मैं माती
सरीर सरोवर बेदी करिहूं, ब्रह्मा वेद उचार
रामदेव संगि भांवरी लैहूं, धनि धनि भाग हमार
सुर तेतीसूं कौतिग आए, मुनिवर सहस अठ्यासी
कहै कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अबिनासी

मन रे राम सुमिरि राम सुमिरि राम सुमिरि भाई।
राम नाम सुमिरन बिनै, बूड़त है अधिकाई।।
दारा सुत गेह नेह, संपति अधिकाई
यामैं कछु नाहि तेरौ, काल अवधि आई
अजामेल गज गणिका, पतित करम कीन्हां
तेऊ उतरि पारि गए, राम नाम लीन्हां
स्वांन सूकर काग कीन्हौ, तऊ लाज न आई
राम नाम अमृत छाड़ि, काहे बिष खाई
तजि भरम करम बिधि निषेद, राम नाम लेही
जन कबीर गुर प्रसादि, राम करि सनेही

पंचकूला के नेचर कैंप थापली में पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने डिजिटल रूप से नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और राशि वन, जिसे अंतरिक्ष वन कहा जाता है, की भी आधारशिला रखी।

ऑक्सी वन की अवधारणा पर बल देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई नीति की घोषणा की है जिसके तहत आठवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल और पालन-पोषण करने पर परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

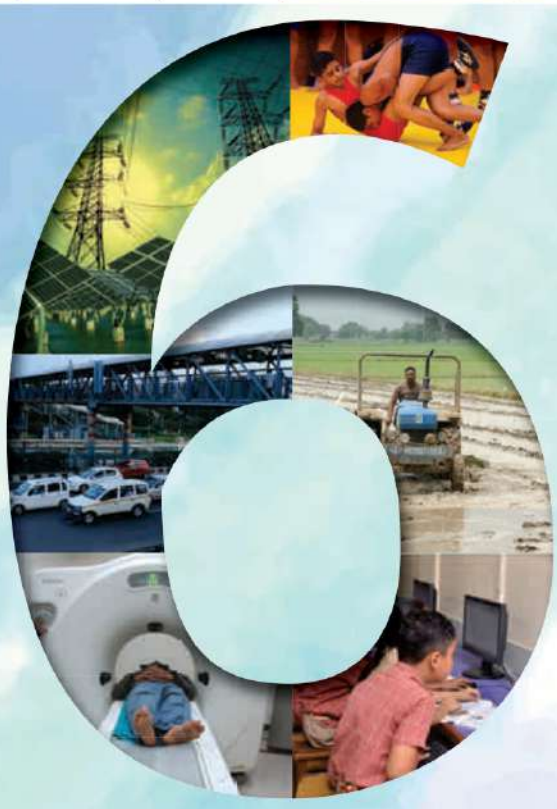

अतुल्य हरियाणा

600 दिन

वर्तमान राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे हुए हैं। 'सबका साथ सबका विकास' के मूल सिद्धांत के अनुरूप राज्य सरकार ने जिस शिद्दत के साथ प्रदेश के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं वे आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं। इतना ही नहीं अन्य राज्यों की सरकारें भी उनसे प्रेरणा लेकर कार्य कर रही हैं।

'सुशासन' के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व व्यवस्था देने का कार्य किया है। नौकरियों में पारदर्शिता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में ढांचागत विकास, सामाजिक सुरक्षा, जल संरक्षण, महिला उत्थान एवं बाल विकास, रोजगार के लिए कौशल विकास, खेल व अन्य अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके बूते आज हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ई-गवर्नेंस, सड़क एवं रेल मार्गों का विस्तार व गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति ने तो पूरे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की कायाकल्प करने का काम किया है। कोरोना काल में जिस सेवा भाव से सरकार ने कार्य किया है उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है।

प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार 1100 करोड़ रूपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ

खेत खलिहान समृद्ध बनाने का संकल्प

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा 11 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
- वर्तमान रबी सीजन में 8472 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर किसानों को 16 हजार करोड़ रुपए का भुगतान।
- वर्ष 2020-21 में रबी व खरीफ फसलों की खरीद पर 29 हजार करोड़ की राशि का किसानों के खातों में भुगतान।
- गन्ने का भाव बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल।
- 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा'' ई-खरीद पोर्टल पर रबी 2020-21 के लिए 9 लाख से अधिक किसानों ने लगभग 62 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया।
- कोविड-19 के दौरान मंडियों में किसानों और आढ़तियों का 10 लाख रुपए का बीमा कवर।
- बैंकों से किसानों के लेन-देन पर स्टाम्प फीस 2000 से घटाकर 100 रुपये की।

बागवानी को बढ़ावा

- ''भावान्तर भरपाई योजना'' में 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित। इनमें 14 सब्जियां, 2 मसाले व 5 फल शामिल।
- बागवानी के 393 फसल समूहों और 1763 बागवानी गांवों की पहचान की। इन फसल समूहों में 150 इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाने के लिए 510 करोड़ रुपए की परियोजना कार्यान्वित।

पशुपालन

- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1344 ग्राम दूध उपलब्धता के साथ हरियाणा देश में पहले स्थान पर।
- पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 53,300 पशुपालकों को 733 करोड़ रुपए ऋण।
- पशुधन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 5 लाख पशुओं का बीमा।

मत्स्य पालन

- प्रदेश में 12 रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम व 20 बायोफ्लक यूनिट स्थापित।
- करनाल तथा चरखी-दादरी में 20 टन प्रतिदिन फीड उत्पादन क्षमता के दो बड़े फीड प्लांट स्थापित।

कल्याणकारी योजनाएं

- गरीब परिवार के उत्थान के लिए 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' शुरू।
- 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत 13.51 लाख परिवारों का पंजीकरण।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक।

स्वायत्तता

- प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर जिला परिषद् का गठन।
- जिला परिषद् के अध्यक्ष को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया। सी.ई.ओ. जिला परिषद् की ए.सी.आर. लिखने की शक्तियां दीं।
- नगर-निगमों के महापौर और नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का सीधा चुनाव करवाने का प्रावधान।
- विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्ति दी।
- महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया।
- पंचायती राज संस्थाओं में मतदाताओं को उनके निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार दिया गया।
- पिछड़ा वर्ग (ए) को पंचायती राज संस्थाओं में मिला आठ प्रतिशत प्रतिनिधित्व।
- पंचकूला में प्रदेश की तीसरी मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पी. एम. डी. ए.) का गठन।
- नगर-निगम, मानेसर और नगर परिषद्, कालका, झज्जर व अंबाला सदर का गठन।
- नगर परिषद् सोनीपत को नगर-निगम तथा बराड़ा, जाखलमंडी, राढौर, इस्माईलाबाद, सढौरा, कुण्डली, बास व सिसाय को नगर पालिका का दर्जा दिया।
- जिला गुरुग्राम के बादशाहपुर को उपमण्डल का दर्जा दिया।
- गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए ''हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण'' गठित।

व्यापारियों को सुविधाएं

- दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकृत करदाताओं को पांच लाख रुपए का बीमा।
- क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत दुकान के नुकसान के लिए पांच लाख से 25 लाख रुपए तक का बीमा।
- योजना के तहत खुदरा विक्रेता और दुकानदार को 3,000 रुपए मासिक पेंशन।

पर्यावरण संरक्षण

- प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रख-रखाव के लिए 2,500 रुपए प्रतिवर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान।
- पर्यावरण संरक्षण और वायु में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए एक वर्ष में तीन करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य।
- सभी शहरों में पांच एकड़ से 100 एकड़ तक की भूमि पर ऑक्सी वन लगाए जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

- 113 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए, इनकी संख्या बढ़कर 136 हुई।
- हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यता बढ़ाकर आजीवन की।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020'' लागू करने की प्रक्रिया शुरू, वर्ष 2025 तक राज्य में पूर्णतः लागू करने का लक्ष्य।
- कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का प्रावधान।
- कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने पर विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा।
- बच्चों और अभिभावकों की टेली-काउंसलिंग के लिए 16 जिलों में उम्मीद केंद्र खोले।
- 15 नए सरकारी कॉलेज खोले, जिनमें 11 लड़कियों के लिए हैं, इनकी संख्या बढ़कर 172 हुई।

ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से सिस्टम में पारदर्शिता आई है और इससे कर्मचारियों में भी संतुष्टि बढ़ी है। पहले कर्मचारियों को तबादलों के लिए चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे।

जलशक्ति अभियान के तहत प्रदेश में बरसाती पानी का सरंक्षण एवं सदुपयोग करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार होने के साथ-साथ हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके।

विकास के..

है। इससे पूर्व 22 जिलों की 163 परियोजनाओं के लिए 1411 करोड़ रुपए की सौगात दी गई थी। इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है।

केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने का है, इस दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसके लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। मिट्टी परीक्षण से लेकर फसल की खरीद तक सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उसमें चाहे फसल के भाव का भुगतान हो या फिर फसल बीमा योजना।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल का संकल्प है कि 'अंतोदय' की भावना से सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनता के कल्याणार्थ खर्च हो जिससे लोगों का जीवन सहज व सरल हो सके। उन्होंने संकल्प दोहराया कि राज्य सरकार 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' की रीति पर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी।

तकनीकी शिक्षा

- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में स्थापित।
- कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र
- पंचकूला और गांव धामलावास (रेवाड़ी) में नये बहुतकनीकी संस्थान स्थापित।
- मुरथल में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार का निर्माण जारी।
- सोनीपत के गांव किलोहड़द में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और सेक्टर-23, पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निर्माणाधीन।
- यमुनानगर के गांव राजपुर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान निर्माणाधीन।
- आई.टी.आई. में दाखिला लेने वाली लड़कियों को 500 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि।

रोज़गार

- योग्यता के आधार पर वर्तमान कार्यकाल में 16 हजार व पिछले कार्यकाल को मिलाकर 8 5 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां।
- सरकारी पदों के आवेदकों के लिए 'एकल पंजीकरण' सुविधा शुरू, जिस पर 4, 41 लाख युवाओं का पंजीकरण हो चुका है।
- एकीकृत रोजगार पोर्टल पर 39,50,500 कौशल युक्त युवाओं, 14,565 नियोजकों तथा 26 जॉब एग्रीगेटरों का पंजीकरण।

उद्योग व व्यापार

- आर्थिक विकास एवं आजीविका के अवसर मुहैया करवाने तथा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ''हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020'' लागू।
- प्रदेश में 2,409 करोड़ रुपए के निवेश से 53 बड़े एवं मध्यम उद्योग लगे। इनमें 97,623 लोगों को रोजगार मिला।
- युवाओं को निजी क्षेत्र के उद्यमों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।

स्वास्थ्य

- कोविड-19 की जांच के लिए टेस्टिंग लैब 13 बढ़कर 42 की गई।
- कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या 13 हजार से बढ़कर लगभग 42 हजार बेड हुई।
- कोविड-19 की जांच की कीमत 3,950 रुपए से घटाकर 450 रुपए किया गया।
- हिसार में 500 बेड तथा पानीपत रिफाइनरी में भी 500 बेड के कोविड अस्पताल शुरू किए गए।
- पी.जी.आई, रोहतक में 400 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई।
- फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का अस्पताल, गुरुग्राम के सिविल लाइन में मैक्काइड फार्मा में 70 बेड का अस्पताल।
- करनाल में 100 ऑक्सीजन बेड का फील्ड अस्पताल, बाबा तारा चेरिटेबल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, सिरसा में 150 बेड का कोविड केयर सेंटर।
- गुरुग्राम में वेदांता ग्रुप के सहयोग से 100 ऑक्सीजन बेड, सेक्टर-67 में वायु सेना के सहयोग से 300 बेड का अस्पताल
- फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, अंबाला, पंचकूला और हिसार में आक्सीजन के छह प्लांट लगाए गए।
- राउरकेला, जमशेदपुर, पानीपत, हिसार, अंगुल, भुवनेश्वर और रूड़की से लगभग 240 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन मंगवाई।
- गांवों में कोरोना टेस्टिंग के लिए 8,000 टीमों का गठन किया गया।
- उपचाराधीन मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट दी गई। किट में डिजिटल थर्मामीटर, थ्री लेयर मास्क, एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाइयां शामिल।
- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की 25 बसों को अस्पतालों में तब्दील किया गया।
- सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज।
- प्राइवेट अस्पतालों में भी बी.पी.एल. परिवारों के कोरोना मरीज़ों का मुफ्त इलाज।
- उपचाराधीन बी.पी.एल. परिवारों के कोरोना मरीजों को इलाज के लिए प्रति मरीज 5,000 रुपए का प्रावधान।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

- मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 750 से बढ़ाकर 1,850 की।
- मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ई.डब्ल्यू.एस के प्रार्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण।
- फरीदाबाद में लगभग 250 करोड़ रुपए से अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज खोला।
- सिरसा, यमुनानगर तथा कैथल में तीन नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत।

खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन

- ओलंपिक खेलों के लिए चुने गए खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख की राशि, इससे 30 खिलाड़ी लाभान्वित।
- ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को छह करोड़, रजत पदक विजेता को चार करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को अढ़ाई करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार का प्रावधान।
- हरियाणा पहली बार करेगा ''खेलो इंडिया-2021'' की मेजबानी। इस प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 12,000 खिलाड़ी भाग लेंगे और 25 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
- अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर किया 20,000 रुपए प्रतिमाह।

स्वच्छ पेयजल

- 'हर घर-नल से जल' योजना में आठ जिलों के शत-प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन।
- 8.80 करोड़ की लागत से दो मल शोधन संयंत्र चालू तथा 10.40 करोड़ की लागत से दो मल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन।
- 2925 करोड़ रुपए से 17 नहर आधारित व एक नलकूप आधारित जलघर स्थापित।
- महाग्राम योजना के तहत 25 बड़े गांवों में 135 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति में बढ़ोतरी तथा सीवरेज सुविधाओं के कार्य शुरू।

सामाजिक सुरक्षा

- साइबर अपराधों से निपटने के लिए गुरुग्राम में देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर स्थापित।
- पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट।
- 'ऑपरेशन संवेदना' के तहत 4 लाख 44 हजार प्रवासी श्रमिकों को 100 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों व 6,600 बसों के माध्यम से सरकार के खर्चे पर उनके गृह राज्यों में पहुंचाया।

संकलन: संगीता शर्मा

लघु, सुक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए जिला स्तर पर ऐसे क्लस्टर स्थापित करने के निर्देश हुए हैं जिनमें नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल सके। इस योजना के तहत युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

ई.ट्रैक्टर पर दी जाने वाली छूट का लाभ 600 किसानों को दिया जाएगा, जिसमें 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके लिए 30 सितंबर 2021 तक ई.ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसान यह लाभ पाने के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री आवास पर जैविक खेती

मुख्यमंत्री मनोहर लाल को खेती-किसानी से बेहद लगाव है। उनके दिन की शुरुआत खेत -खलिहान से ही होती है। खेती के प्रति उनके लगाव का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे न केवल खेत में सब्ज़ियों की देखरेख करते हैं, बल्कि अपनी रसोई में पकाने के लिए सब्ज़ियां भी तोड़ कर लाते हैं।

चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में इन दिनों जैविक सब्ज़ियों की पैदावार हो रही है। इनमें खीरा, टमाटर, भिंडी, घीया, तोरई और करेले जैसी सब्ज़ियां उगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुबह की शुरुआत इनकी देख-रेख के साथ करते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर निराई-गुड़ाई का काम भी कर लेते हैं। वे अक्सर रसोई में खुद खाना बना लेते हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल की रोहतक जिले के बनियानी गांव में पुश्तैनी ज़मीन है, जहां वे खुद भी खेती करते रहे हैं। उन्होंने कालेज की पढ़ाई के दौरान खूब खेती की है। आज भी खेती से उनका जुड़ाव कम नहीं हुआ है।

तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा है कि आज के समय में पानी के सीमित स्रोतों को देखते हुए जल संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने आवश्यक हो गए हैं। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है जिसके तहत किसानों को धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने का आह्वान किया गया था। पिछले वर्ष 94 हज़ार एकड़ भूमि पर धान नहीं बोया गया था। इस वर्ष दो लाख एकड़ का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाज़ारे का उत्पादन अधिक हो रहा है, इसलिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान बाज़रे के स्थान पर दालें और तिलहन उगाएगा उसे सरकार की ओर से 4 हज़ार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

जल बचाने के लिए छोड़ दी धान की खेती

किसान जल संरक्षण को गंभीरता से लेने लगे हैं, यही वजह है कि बहुत से किसानों ने धान फसल से दूरी बना ली है। प्रदेश के अनेक किसानों ने परंपरागत फसल की जगह सब्ज़ी व फल की पैदावार पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्य सरकार ने धान की जगह अन्य फसल लगाने वाले किसानों को 7000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है।

सिरसा जिले के अनेक किसान धान को छोड़कर सब्ज़ियां उगाने लगे हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप और वॉटर स्प्रिंगकलर सिस्टम लगाए हैं, जो जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। सिरसा जिला से घग्गर नदी गुजरती है लेकिन नदी में जल बारिशों पर निर्भर करता है। वहीं लगातार परंपरागत फसल लेने व अत्याधिक मात्रा में जल दोहन के कारण जिले का भूमिगत जलस्तर ढाई सौ फिट पर चला गया। जो किसानों और आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय है।

गांव झोरड़ नाली के किसान मुकेश कंबोज धान की खेती छोड़कर अपनी साढ़े तीन एकड़ भूमि पर सब्ज़ियों के साथ नर्सरी लगा रहे हैं। गांव के अन्य किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। करीब 650 किसान उनके द्वारा लगाए ड्रिप सिस्टम को देख चुके हैं, कइयों ने इस तकनीक पर काम भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए सैलरों से धान का जला हुआ भूसा खेतों में डाला गया। भूसे में पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। जिससे मिट्टी की सतह नरम पड़ने लगती है, जो अत्याधिक मात्रा में पानी को सोखती है।

केलणिया गांव के किसान राजपाल ने अपनी साढ़े तीन एकड़ जमीन में घीया, तोरी, टमाटर और टिंडे लगाए हैं। वे कहते हैं भूल कर भी धान और गेहूं नहीं लगाएंगे। धान से पानी की खपत ज्यादा होती थी और आमदनी मंडी भाव पर निर्धारित होती है। कई बार तो पानी के अभाव में फसल बर्बाद हो जाती थी, इसलिए बागवानी फसल उगानी शुरू की। इससे पानी की भी बचत हो रही है, और आमदनी भी पहले के मुकाबले बढ़ी है।

खेरिका गांव के किसान सुरेंद्र धारीवाल ने बताया कि जिले में पानी का चौवा ढाई सौ फुट नीचे चला गया है। हर साल साठ फुट नीचे जा रहा है। परंपरागत धान की फसल की जगह पिछले साल से 11 एकड़ भूमि पर सब्ज़ियां लगाई हैं। इससे जल की भी बचत हो रही है। खेत में गांव के ही 60 से 70 मजदूरों को काम मिला है।

अलीपुर टिट्टू खेड़ा गांव के किसान विपुल परंपरागत खेती को छोड़कर आर्गेनिक सब्ज़ियां उगा रहे हैं। गांव में ही अमृत आहार नाम से दाल और सब्ज़ियों का स्टोर चला रहे हैं। उन्होंने 5 एकड़ जमीन पर आर्गेनिक सब्ज़ी लगाई है। इसमें अपेक्षाकृत लाभ भी अधिक मिलता है। सब्ज़ी और दालों की मांग हर मौसम में बनी रहती है।

केलणिया गांव के किसान संत लाल ने बताया कि उसके पास साढ़े तीन एकड़ भूमि है जिस पर भिंडी, तौरी, घीया, कद्दू और अन्य बेल वाली सब्ज़ियां लगाई है। एक एकड़ में मूंग लगाया है। मूंग अच्छा हुआ तो मुनाफा अधिक मिलेगा। बागवानी की ओर ध्यान दिया है जिससे फायदा तो अधिक होगा ही होगा जल का संरक्षण भी होगा।

-मनोज कुमार

शहद कारोबारियों के लिए मधुक्रांति पोर्टल

मधुक्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल है और इस पोर्टल की स्थापना भारत में हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा की गई है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत संचालित किया गया है। यह डिजिटल प्लेटफार्म शहद और मधुमक्खी के उत्पादों के ट्रैसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है। साथ ही यह पोर्टल, शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में मदद करेगा।

पोर्टल की स्थापना के उद्देश्य

- अच्छी गुणवत्ता का शहद उपलब्ध कराना।
- मधुमक्खी पालन का डाटा-बेस तैयार करना।
- किसानों की आय बढ़ाना।
- निर्यात को बढ़ावा देना।

पोर्टल पर 'पंजीकरण'

यह पोर्टल शहद उत्पादन, विपणन शृंखला और बिक्री में शामिल सभी हितधारकों के डेटाबेस को मैंटेन करेगा। इससे अंतराष्ट्रीय बाज़ारों में शहद की पहुंच बढ़ेगी तथा इससे हितधारकों से आसानी से संपर्क किया जा सकता है। इस डिजिटल प्लेटफार्म के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का इंडियन बैंक, तकनीकी और बैंकिंग भागीदार है। इस प्लेटफार्म को लागू करने के लिए बैंक ने नैशनल बी बोर्ड के साथ एक समझौता किया है। मधुक्रांति पोर्टल पर 'पंजीकरण' हेतु हर जिले में हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय टीम गठित की गई है जोकि हरियाणा राज्य के मधुमक्खी पालकों को पंजीकरण के बारे में बताएगी व उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी। सभी मधुमक्खी पालक/एफ.पी.ओ./सोसाइटी व शहद विपणन में कार्यरत हितधारक इस पोर्टल www.allbankcare.in/nbb/ पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्यान विभाग, हरियाणा द्वारा गठित जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय टीम 15 जून से 15 जुलाई तक सभी मधुमक्खी पालकों व

अन्य हितधारकों को पंजीकरण करवायेगी ताकि भविष्य में विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

क्या है ज़रूरी

- इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए न्यूनतम दस मधुमक्खी बक्से होना अनिवार्य है।
- पोर्टल पर पंजीकरण की अवधि पांच साल तक मान्य होगी।
- पांच साल के बाद दोबारा से पंजीकरण को नवीनीकरण करवाया जा सकता है।
- पोर्टल पर पंजीकरण के बाद मधुमक्खी पालक/एफ.पी.ओ. /सोसाइटी/ फर्म की पहचान वैध हो जाएगी और इन सभी को एन.बी.बी. द्वारा जारी की गई दिशा-निर्देशों को मानना होगा।
- यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो पंजीकृत व्यक्ति व समूह का पंजीकरण अमान्य किया जाएगा।
- पोर्टल पर पंजीकरण के बाद सभी व्यक्ति व समूह को वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खी पालन को अपनाना होगा।
- यदि किसी भी मधुमक्खी पालन की कालोनी में बीमारी आती है तो उसे एन.बी.बी. को रिपोर्ट करना होगा तथा उसी के दिशा-निर्देश को मानना होगा।
- दवाईयों व रसायनिक तत्वों का इस्तेमाल केवल विशेषज्ञ व वैज्ञानिक की अनुमति से ही कर सकते हैं।
- उन्हें केवल पक्का शहद ही छत्ते से निकालना होगा और स्टेनलैस स्टील के मधुनिकासन यंत्र ही इस्तेमाल करना होगा।
- शहद का भंडारण भी फुड ग्रेड प्लास्टिक के बरतनों व बाल्टियों में करना होगा।
- इस पोर्टल पर पंजीकरण केवल उसी का होगा जिसके पास 10 मधुमक्खी बक्से हैं जोकि एपिस सिराना, एपिस मैलिफेरा, ट्रीगोना, स्टींगलैस मधुमक्खियों के हो सकते हैं।
- पंजीकृत मधुमक्खी पालक, सोसाईटी, कम्पनी को अपने

दस्तावेज बनाने होगें ताकि फार्म स्तर पर शहद की टरैसेबिल्टी की जा सके।

- पंजीकरण के लिए एक पासपोर्ट साईज फोटो व आधार कार्ड अनिवार्य है।

पंजीकरण के लिए फीस

10 फ्रेम की मधुमक्खी कालोनी के लिए	
10 फ्रेम मधुमक्खी कालोनी के बक्से	पंजीकरण हेतु फीस रुपए
10-100	250/-
101-250	500/-
251-500	1,000/-
501-1000	2,000/-
1,001-2,000	10,000/-
2,001-5,000	25,000/-
5,001-10,000	1,00,000/-
10,000 से अधिक	2,00,000/-

पंजीकरण में 20 प्रतिशत की छूट

फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाएगी। यदि पंजीकरण के बाद कोई व्यक्ति अपनी कालोनी बढ़ाता है तो उसे सूचित करना आवश्यक है। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद यदि मधुमक्खी कालोनी की संख्या कम होती है तो तब फीस वापिस नहीं होगी। एन.बी.बी. के सदस्यों को पंजीकरण में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पंजीकरण की फीस वापिस नहीं होगी। पंजीकृत व्यक्ति को अपनी परिक्षण का अनुभव भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पंजीकरण के बाद सभी पंजीकृत व्यक्तियों व समूहों को एक विशेष पंजीकरण नंबर एन.बी.बी. द्वारा जारी किया जाएगा। इसी नंबर को सभी मधुमक्खी पालक/सोसाइटी/समूहों द्वारा अपने सभी बक्सों, उपकरणों पर अंकित करना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। पंजीकृत मधुमक्खी पालक/एफ.पी.ओ. / सोसाइटी/फर्म को सिर्फ़ एक ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र मिलेगा और यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाता है तो डूप्लीकेट के लिए 250/-रुपए के साथ एफ.आई.आर. की कॉपी भी चाहिए होगी। मधुमक्खी पालक को अपनी पिछली साल की कालोनी व उत्पादन का ब्यौरा देना होगा। यदि कोई मधुमक्खी पालक गलत जानकरी देगा तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति/समूहों की अपायरी व इससे संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पर खुला रहेगा।

-संगीता शर्मा

कोविड-19 हेल्थकेयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 'विशेष क्रैश-कोर्स' के तहत देशभर के एक लाख युवाओं को कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। कैथल, रोहतक और यमुनानगर में क्रैश-कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रदेश के किसानों की ख़राब पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इस वर्ष एक लाख एकड़ भूमि को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार किसानों के साथ मिलकर खराब जमीन को ठीक करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।

पदक विजेताओं को खेल विभाग में नौकरी

अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी दी जाएगी ताकि उनके अनुभवों से नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। खेलों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने बेहतरीन पोलिसी बनाई है। इसके तहत खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ मेडल अनुसार नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए खेल स्टेडियमों का नवीनीकरण करने के साथ साथ ग्रामीण व शहरी स्तर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने ओलम्पिक पदक विजेता खिलाड़ियों से चंडीगढ़ आवास पर मुलाकात की। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी लगाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार उन्हें डेपुटेशन पर भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि अच्छा खिलाड़ी कोच बनेगा तो खेलों को प्रमोट किया जा सकेगा और मेडलिस्ट वर्ग से युवा खिलाड़ियों को भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों को ओलम्पिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को जिस विभाग में बेहतर ऑफर मिलें उसमें आगे बढ़ने के लिए शामिल हो जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब खिलाड़ी मैट की ओर बढ रहे हैं लेकिन इसमें धन की अधिक आवश्यकता होती है। मैट पर आने के बावजूद खिलाड़ी स्वभाविक खेल की भावना न छोड़ें। पहलवान का सही अभ्यास अखाड़े की मिट्टी में ही होता है। इसलिए युवाओं को मिट्टी से लगाव रखना चाहिए। मेट से मिट्टी की ओर रहने वाले खिलाड़ी दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनेंगे।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी देश के लिए अधिक मेडल लाने की भावना के साथ खेलें और अपने अभिभावकों के साथ देश व प्रदेश का नाम रोशन करें। इसके अलावा 'खेलो इंडिया' प्रतियोगिता से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

टोक्यो ओलम्पिक के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन

खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि आगामी टोक्यो ओलम्पिक खेलों के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की राशि तैयारी के लिए उपलब्ध करवाई गई है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने पर 6 करोड़ रुपए, रजक पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेता को 2.50 करोड रुपए की नकद राशि प्रदान की जाएगी।

-संवाद ब्यूरो

मिल्खा सिंह की 'अंतिम दौड़'

साठ के दशक में उड़न सिक्ख के नाम से मशहूर हुए मिल्खा सिंह नहीं रहे। 91 वर्षीय मिल्खा आज की युवा पीढ़ी के लिए शायद अनजान बने रहते यदि 2013 में उन पर 'भाग मिल्खा भाग' फिल्म न बनती। जिसमें फरहान अख्तर ने उनके चरित्र को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से निभाया था। 1960 के रोम ओलम्पिक में चौथे स्थान पर रहे मिल्खा चन्द सेकंड से चूक गये वरना ओलम्पिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय धावक बन जाते। उसके बाद ही पूरे देश में वे दौड़ के पर्याय बन गए। उनको 'उड़न सिक्ख' ' की उपाधि किसी भारतीय ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा दी गयी थी। ओलम्पिक पदक जीतने का गौरव वे भले ही हासिल न कर सके हों लेकिन एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा ने अनेक स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वाधीनता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी ही वह खेल था जिसमें भारत का दबदबा था लेकिन 1956 , 60 और 64 के ओलम्पिक खेलों के बाद एथलैटिक के क्षेत्र में मिल्खा ने ही भारत को पहचान दिलवाई। साठ के दशक में विश्व स्तर के धावकों के समकक्ष माने जाने वाले मिल्खा को 2001 में अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई जिसे उन्होंने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह बहुत देर से दिया गया।

इस बार अधिक पदकों की उम्मीद

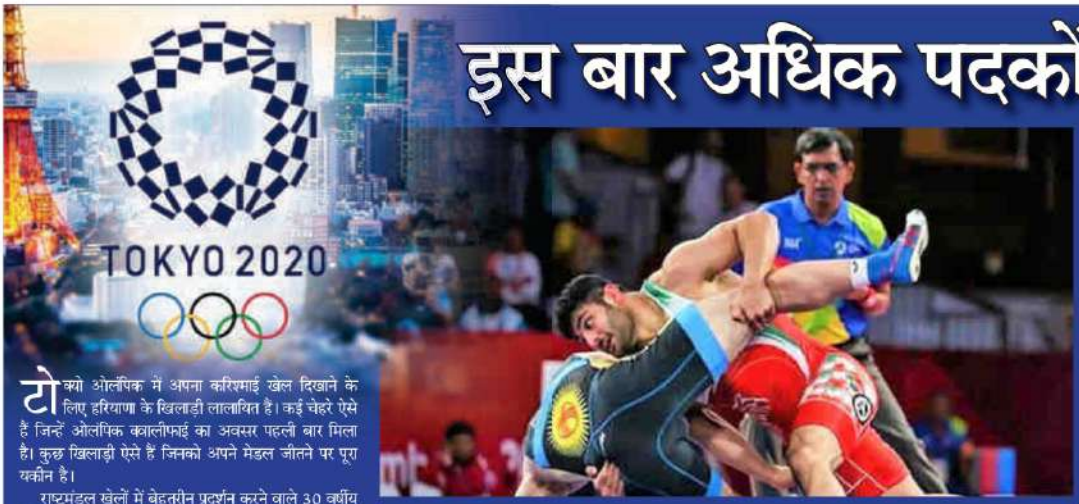

टोक्यो ओलंपिक में अपना करिश्माई खेल दिखाने के लिए हरियाणा के खिलाड़ी लालायित है। कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें ओलंपिक क्वालीफाई का अवसर पहली बार मिला है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अपने मेडल जीतने पर पूरा यकीन है।

राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 30 वर्षीय नीरज चौपड़ा का यह पहला ओलंपिक है। वे कहते हैं ओलंपिक में मेडल के लिए जितनी अभ्यास की आवश्यकता होती है उतनी ही माइंड सेट की। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं।

निशानेबाजी में उभरती महिला यशस्विनी देशवाल अभ्यास कर पदक पर निशाना साधने की कोशिश करती दिखाई पड़ रही हैं। उन्होंने दिल्ली में गत वर्ष हुई आईएसएसएफ में लगातार दो पदक जीत कर सबको हैरान कर दिया था, वह 10 मीटर की निशानेबाज है। उन्हें टॉप निशानेबाज मनु भाकर के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता था। फ्री स्टाईल कुश्ती में 65 किलो के बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल में चुनौती देंगे। वे कहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से उन्हें काफी सुविधाएं मिल रही हैं। वह रजत नहीं, कांस्य नहीं स्वर्ण पदक पर नजर रखकर मेहनत कर रहे हैं।

मुक्केबाजी 69 किलो वजन वर्ग में भारत की उम्मीद विकास कृष्ण है। वे लगातार मुक्केबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। विकास 2010 में एशियन खेलों में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। स्टॉर मुक्केबाज मनीष कौशिक कहते हैं कि मंजिल को हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर करनी पड़ती है। बड़े कंपेटीशन के लिए परफेक्ट होकर जाना पड़ता है। हमारा हौसले बुलंद हैं।

कुश्ती में उभरती खिलाड़ी अंशु मलिक कहती है कि हर बड़े कंपीटिशन की तैयारी को लेकर मेंटल व फिजिकल स्टेटस को एक साथ लेकर खेलना पड़ता है। निशानेबाज मनु भाकर कहती हैं कि राज्य सरकार ने ट्रेनिंग के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। उनकी मेहनत रंग लाएगी, इसके लिए वे भरपूर कोशिश कर रही है।

कोच कुलदीप मलिक कहते हैं ओलंपिक के लिए हरियाणा के खिलाड़ी जिस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं उन्हें देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि इस बार पदकों की संख्या में काफी इजाफा होगा।

-सुरेन्द्र सिंह मलिक

ओलंपिक के लिए भारतीय दल में हरियाणा से 30 खिलाड़ी

टोक्यो ओलंपिक खेलने जा रहे देश भर के कुल 121 खिलाड़ियों में से 30 अकेले हरियाणा प्रदेश से हैं। इन खिलाड़ियों को बेहतरीन कोच प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मेडल जीते जा सकें।

भारतीय महिला हाकी टीम में हरियाणा से नौ लड़कियों का चयन हुआ है। इतना ही नहीं, भारतीय पुरुष हाकी टीम में भी दो खिलाड़ी हरियाणा के सोनीपत व कुरुक्षेत्र से हैं।

देश की कुल आबादी की तुलना में प्रदेश की आबादी महज दो प्रतिशत है। बावजूद इसके ओलंपिक के लिए लगभग 25 प्रतिशत खिलाड़ी हरियाणा से चयनित होना राज्य सरकार की कारगर खेल नीति को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है राज्य सरकार ने ओलंपिक के लिए चयनित हुए खिलाड़ियों को पहली बार पांच- पांच लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई है ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें।

खेलो इंडिया प्रतियोगिता

खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि खेलों के क्षेत्र में प्रदेश के लिए इस वर्ष दो बड़े इवेंट ओलंपिक और खेलो इंडिया आ रहे हैं। खेलो इंडिया 21 से 30 नवंबर तक पंचकूला व आसपास साथ लगते जिलों के आयोजित किया जाएगा। जिसमें ब्रिक्स देशों सहित हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे।

उन्होंने कहा जापान ओलंपिक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार खेलो इंडिया को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को व्यवस्थ समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

टोक्यो ओलंपिक के रेफरी अशोक से बातचीत

टोक्यो ओलंपिक के लिए बतौर रेफरी चयनित हुए अशोक कुमार का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। अशोक सोनीपत जिले के गांव कासंडी के रहने वाले हैं। वे फिलहाल वायु सेना 20 विंग में वारंट ऑफिसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

चयन होने पर कैसा अनुभव कर रहे हैं?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका एक बार फिर चयन हुआ है। वे 26 जुलाई के आसपास टोक्यो के लिए रवाना होंगे। कुश्ती का कार्यक्रम संभावित एक अगस्त से 4 अगस्त होगा। यह मेरे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है।

चयन होने की सूचना कैसे मिली

इसकी जानकारी उन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रैसलिंग द्वारा भेजे गए ई-मेल से प्राप्त हुई। भारतीय कुश्ती संघ ने भी इसे बारे में सूचित किया था। कई वर्षों से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेफरी की जिम्मेदारी निभाता आ रहा हूं।

चयन प्रक्रिया में किस पर रहता जोर

टोक्यो ओलंपिक के लिए सर्वश्रेष्ठ 100 रेफरियों का चयन हुआ है। बड़ी टूर्नामेंट में निर्णायक मंडली नजर रखती है कि कौन रेफरी सही निर्णय दे रहा है, किसकी कम गलतियां कर रहा है। दूसरे की कितनी गलतियां नोट कर रहा है। कोई पक्षपात तो नहीं। दिसंबर माह में चयन प्रक्रिया के बारे में पहली सूची जारी हुई थी जिसके बाद यूरोप और एशिया में आयोजित सभी प्रतियोगिताओं के अलावा सभी ओलंपिक क्वालीफायर राउंड में शामिल होने वाले रेफरियों को हर स्तर पर परखने के बाद दोबारा सूची जारी की गई है।

कोच का प्रशिक्षण कहां से लिया

पटियाला से कुश्ती में एनआईएस का डिप्लोमा किया है। वर्ष 2005 में रेफरी की ट्रेनिंग ली। उन्हें दूसरी बार ओलंपिक में बतौर रेफरी के लिए चुना गया है। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी अपॉइंटिंग की थी। वह भारत के पहले और एकमात्र रेफरी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है।

इस क्षेत्र में कब कदम रखा

उन्होंने 8 साल की उम्र में पहलवान के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। विभिन्न कारणों से वे वांछित लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। एनआईएस कोचिंग डिप्लोमा पूरा करने के बाद कुश्ती में वायु सेना में कोच के रूप में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेफरी के रूप में दोहरा काम शुरू किया।

राज्य सरकार एरोस्पेस व डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रदेश को उत्तर भारत में एक अग्रणी 'एमआरओ' हब (मैंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब) बनाना चाहती है। इससे न केवल नागरिक विमान बल्कि रक्षा विमान लाभान्वित होंगे।

स्थानीय निकायों को उनके वित्तीय और कार्यात्मक सशक्तिकरण के मामले मजबूत करने के लिए अंतर-जिला परिषद का गठन किया है। वित्त विभाग द्वारा योजना के सिद्धांत पर स्थानीय निकाय विकास निधि पोर्टल को विकसित किया गया है।

शिवालिक की पहाड़ियों में पर्यटन

शिवालिक की पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अनेक योजनाओं पर कार्य शुरू किया है। मोरनी हिल्स के टिक्करताल क्षेत्र में आयोजित एडवेंचर गतिविधियों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं भाग लेकर लोगों का उत्साहवर्धन करने का काम किया और कहा कि टिक्करताल में आयोजित होने वाली साहसिक गतिविधियां आसान एवं सुरक्षित हैं।

पर्यटन क्षेत्र मोरनी हिल्स के टिक्करताल में पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रोलर जॉबिंग, ई-हैड्रोफोइएल, जेट स्कूटर, पैरा सेल्लिंग और ट्रेकिंग जैसे एडवेंचर खेलों के आयोजन को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद ताल में वाटर मोटर स्कूटर की सवारी की। मुख्यमंत्री ने हॉट-एयर बैलून में उड़ान भरी तो उपस्थित ग्रामीणों ने हाथ हिला कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने जेट स्कूटर को अपने जीवन मे पहली बार चलाया है।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस दौरान साहसिक खेलों के क्रम में बोट रोइंग के खेल का भी रोमांचक प्रदर्शन किया गया और उन्होंने रोइंग करने वाले नाविकों से भी बातचीत की। बोट रोइंग का खेल केरल में सबसे ज्यादा खेला जाता है और अब यह खेल टिक्करताल में भी आने वाले आगंतुकों को देखने व खेलने को मिलेगा। इस खेल में नाविकों के हौसला-अफजाई व जोश भरने के लिए ड्रम बजाया जाता है ताकि वे ताल मिला कर तेजी से अपनी नाव को चलाये।

पंचकूला को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने टिक्करताल में साहसिक खेल गतिविधियों का अवलोकन कर युवाओं का हौसला बढ़ाने के साथ पंचकूला को सांस्कृतिक, मेडिकल, वन्य जीव एवं अन्य क्षेत्रों में विकसित करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।

साहसिक खेल गतिविधियों का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक खेल गतिविधियों के लिए लोगों को बहुत दूर मनाली आदि क्षेत्रों में जाना पड़ता है। शिवालिक पहाड़ियों के बीच मोरनी हिल्स एरिया में इस तरह की गतिविधियां शुरू होने से लोगों को न केवल रोमांचक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, बल्कि इनसे आस-पास के क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। इस क्षेत्र का भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से प्रचीन इतिहास है।

उन्होंने कहा कि पंचकूला में पर्यटन सूचना केंद्र बनाया जाएगा। यात्री निवास की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। पंचकूला दर्शन के लिए पांच बसें लगाने की योजना है। पिंजौर में हॉट एयर बैलून का प्रयोग शुरू किया जाएगा। इससे नागरिक न केवल पिंजौर गार्डन बल्कि मोरनी, टिक्कर लेक व पंचकूला के अन्य स्थलों के भी दर्शन कर पाएंगे। हॉट एयर बैलून की सुविधा देशभर में केवल पांच-छह स्थानों पर ही है।

मिल्खा सिंह के नाम पर होगा पैराग्लाईडिंग क्लब

पैराग्लाईडिंग के लिए आस-पास के युवाओं को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन गतिविधियों के संचालन के लिए क्लब का गठन किया जाएगा। इसका नाम फ्लाईंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर होगा।

पैराग्लाईडिंग के लिए मोरनी एक बेहद उपयुक्त स्थल साबित होगा। इससे आस-पास के गांवों में रोज़गार बढ़ेगा और प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

कालका से कलेसर पर्यटन रूट

कालका से कलेसर तक का क्षेत्र पर्यटन रूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। नाडा साहेब और मनसा देवी तीर्थ स्थलों के विकास के लिए केंद्र से 49 करोड़ की राशि जारी हुई है जिससे इन स्थलों पर कार्य करवाए जा रहे हैं। आदिबद्री के लिए 52 करोड़ की राशि मिली है जिससे वहां पर भी कार्य करवाए जा रहे हैं। इस रूट से मोरनी को भी जोड़ा जा रहा है। इसमें माणेगढ़, लोहगढ़ में बना किला भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। टूरिज्म के हिसाब से और स्थानों पर भी गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

-संवाद ब्यूरो

जल संचय हो ध्येय हमारा

जल की कमी से जूझ रहा है 21वीं सदी का जग सारा,
जल संचय हो ध्येय हमारा, जल संचय ही नारा।
व्यर्थ बहाओगे आज तो कल बूंद-बूंद को तरसोगे,
बादल से करोगे पुकार कि अब तुम फिर कब बरसोगे।
ज़रुरत अनुसार उपयोग करना ही लक्ष्य हो हमारा,
जल संचय हो ध्येय हमारा जल संचय ही नारा।।
स्वच्छता और जल का एक अनूठा रिश्ता है,
तभी बचेगा कल का जल अगर आज सच्ची निष्ठा है।
संयुक्त प्रयासों से क्यों न हो स्वच्छ संसार हमारा,
अगर जल संचय हो ध्येय हमारा जल संचय ही नारा।।
कूड़ा न फेंको इधर-उधर जाने या अनजाने से,
दूषित होता है नदियों का जल इसके संपर्क में आने से।
कूड़े का उचित निस्तारण ही एकमात्र सहारा,
जल संचय हो ध्येय हमारा जल संचय ही नारा।।

जल और स्वच्छता की अहम भूमिका कोरोना सी महामारी में,
हाथ धोने की अलख जगा दी देखो दुनिया सारी में।
भविष्य की मुश्किलें भी टलेगी जैसे कोरोना है हारा,
जल संचय हो ध्येय हमारा जल संचय ही नारा।।
अपशिष्ट जल का पुनरूपयोग ही शुद्ध जल की खपत रोकेगा,
भूजल भी इतनी तेज़ी से कभी नहीं फिर सोखेगा।
भूजल का स्तर बढ़ाने को पूरा होगा लक्ष्य हमारा,
जल संचय हो ध्येय हमारा जल संचय ही नारा।।
मानसून में वर्षा जल को संरक्षित हमें अब करना है,
खाली पड़े तालाब कुँओं को वर्षा जल से भरना है।
जलाभाव की इस समस्या से पाना है छुटकारा,
जल संचय हो ध्येय हमारा जल संचय ही नारा।।

- ज्योतिप्रसाद

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com